



**आधुनिकीकरण और ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन:
मुरादाबाद जनपद में परिवार, जाति एवं सामाजिक संबंधों का विश्लेषण**

शोधार्थी

अमर पाल

महाराजा हरिश्चन्द्र पी.जी. कॉलेज

मुरादाबाद

Email- amarpal22222@gmail.com

शोध निर्देशक

डॉ. मुकेश मोहन

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग)

महाराजा हरिश्चन्द्र पी.जी. कॉलेज

मुरादाबाद

Email- mmohansocio@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.22033392>

सारांश

यह शोध-पत्र मुरादाबाद जनपद के ग्रामीण समाज में आधुनिकीकरण से उत्पन्न परिवर्तनों का परिवार, जाति और सामाजिक संबंधों के तीन केंद्रीय आयामों पर विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का वैचारिक आधार आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण-पाश्चात्यीकरण, संरचनात्मक परिवर्तन तथा ग्रामीण-नगरीय सातत्य की अवधारणाओं में निहित है। शिक्षा, संचार प्रौद्योगिकी, गैर-कृषि रोजगार, प्रवासन, बाजार-संपर्क और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को परिवर्तन के प्रमुख प्रेरक कारकों के रूप में देखा गया है। अभ्यास हेतु 300 ग्रामीण उत्तरदाताओं का एक उदाहरणात्मक, स्तरीकृत डेटासेट निर्मित किया गया है; अतः इससे प्राप्त संख्यात्मक निष्कर्षों को वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। वर्णनात्मक प्रतिशत, औसत, मानक विचलन तथा संकेतात्मक सहसंबंध के माध्यम से परिणामों को समझाया गया है। उदाहरणात्मक निष्कर्ष बताते हैं कि एकल परिवारों की वृद्धि, घरेलू निर्णयों में महिलाओं और युवाओं की बढ़ती भागीदारी, जातिगत पेशों की बाध्यता में कमी तथा शिक्षा और डिजिटल माध्यमों पर आधारित नए संबंधों का विस्तार स्पष्ट है। फिर भी विवाह, सामाजिक प्रतिष्ठा, संसाधनों की उपलब्धता और राजनीतिक गुटबंदी में जाति का प्रभाव बना हुआ है। परिवर्तन रैखिक न होकर चयनात्मक है: ग्रामीण परिवार आधुनिक आर्थिक व्यवहार अपनाता है, पर भावनात्मक और अनुष्ठानिक स्तर पर नातेदारी को बनाए रखता है। अध्ययन समावेशी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, गैर-कृषि कौशल, महिला समूहों, अंतर-समुदाय संवाद और ग्राम-स्तरीय संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करने की अनुशंसा करता है।

मुख्य शब्द: आधुनिकीकरण, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, परिवार, जाति, सामाजिक संबंध, मुरादाबाद।

प्रस्तावना

भारतीय ग्रामीण समाज को प्रायः परंपरा, कृषि, जाति और नातेदारी पर आधारित स्थिर व्यवस्था के रूप में देखा गया, किंतु ऐतिहासिक रूप से गाँव कभी पूर्णतः बंद या अपरिवर्तनशील इकाई नहीं रहे। औपनिवेशिक प्रशासन, परिवहन, भूमि-संबंध, शिक्षा, लोकतांत्रिक राजनीति और बाजार ने निरंतर ग्रामीण संस्थाओं का पुनर्गठन किया है। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज, हरित क्रांति, आरक्षण, सड़क और विद्युत विस्तार, विद्यालयीकरण, कल्याणकारी योजनाओं तथा मीडिया ने इस गति को बढ़ाया। श्रीनिवास (1966) ने सामाजिक गतिशीलता को संस्कृतिकरण और पाश्चात्यीकरण से समझाया, जबकि



योगेन्द्र सिंह (1973) ने भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण को परंपरा के विनाश के बजाय उसके पुनर्संयोजन की प्रक्रिया माना।

मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ कृषि-आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संपर्क धातु-शिल्प, व्यापार, परिवहन तथा निकटवर्ती नगरीय बाजारों से है। जनगणना का जिला हैंडबुक गाँव-नगर वितरण, सुविधाओं, जनसंख्या, कार्य-संरचना और सामाजिक संरचना के अध्ययन हेतु आधारभूत संदर्भ प्रदान करता है (भारत की जनगणना, 2011a, 2011b)। सड़क, मोबाइल फोन, निजी शिक्षा, दैनिक आवागमन और खाड़ी अथवा महानगरों की ओर श्रम-प्रवासन ने गाँव की सीमाओं को सामाजिक रूप से अधिक पारगम्य बनाया है। इन प्रक्रियाओं का प्रभाव हर वर्ग और जाति पर समान नहीं है; भूमि, शिक्षा, लिंग, आयु और नेटवर्क की असमानताएँ आधुनिक अवसरों तक पहुँच को प्रभावित करती हैं।

जिला जनगणना पुस्तिका मुरादाबाद के ग्रामीण अधिवासों, बुनियादी सुविधाओं तथा जनसांख्यिकीय विविधता को गाँव-स्तर तक दर्ज करती है। ऐसे आँकड़े सामाजिक परिवर्तन की स्थानीय पृष्ठभूमि समझने में उपयोगी हैं, किंतु वे परिवार के भीतर सत्ता, जाति-आधारित व्यवहार या दैनिक सामाजिक संबंधों के व्यक्तिनिष्ठ अनुभवों को सीधे नहीं मापते। दूसरी ओर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा महिला भागीदारी के व्यापक संकेतक देते हैं, पर जिला-विशिष्ट सामाजिक अंतःक्रिया का सूक्ष्म विवरण सीमित है (अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, 2021; सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2024)।

यह अध्ययन ग्रामीण समाज को “परंपरा बनाम आधुनिकता” की सरल द्वैधता से बाहर समझने में सहायता करता है। परिवार आर्थिक दृष्टि से छोटा हो सकता है पर विवाह, उत्तराधिकार और संकट में विस्तृत नातेदारी सक्रिय रह सकती है। जातिगत पेशा कमजोर हो सकता है पर विवाह और स्थानीय राजनीति में जाति प्रभावी रह सकती है। इसी प्रकार डिजिटल नेटवर्क नए संबंध बनाते हैं, पर डिजिटल असमानता नए बहिष्करण भी उत्पन्न करती है। यह दृष्टि जिला प्रशासन, पंचायत, शिक्षा विभाग, स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास संस्थाओं के लिए अधिक यथार्थवादी हस्तक्षेप सुझाती है।

सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक आधार

आधुनिकीकरण की अवधारणा

आधुनिकीकरण को औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, साक्षरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बाजार विस्तार, नौकरशाही और उपलब्धि-आधारित स्थिति की ओर परिवर्तन से जोड़ा गया है। लर्नर (1958) ने संचार और मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को आधुनिक समाज की शर्त माना, जबकि इंकल्स और स्मिथ (1974) ने आधुनिक व्यक्ति में समय-अनुशासन, योजना और नई सूचनाओं के प्रति खुलापन रेखांकित किया। भारतीय संदर्भ में यह प्रक्रिया पश्चिमी प्रतिरूप की प्रतिलिपि नहीं है। योगेन्द्र सिंह (1973) के अनुसार आधुनिक संस्थाएँ स्थानीय परंपराओं के साथ अंतःक्रिया कर मिश्रित रूप उत्पन्न करती हैं।

संस्कृतिकरण, पाश्चात्यीकरण और प्रभुत्वशाली जाति

श्रीनिवास (1966) का संस्कृतिकरण सिद्धांत निम्न या मध्य जातियों द्वारा उच्च मानी गई जीवन-शैलियों को अपनाकर प्रतिष्ठा बढ़ाने की प्रक्रिया बताता है। पाश्चात्यीकरण शिक्षा, विधि, तकनीक और संस्थागत मूल्यों के प्रभाव को इंगित करता है। प्रभुत्वशाली जाति की अवधारणा भूमि, संख्या, शिक्षा और राजनीतिक शक्ति के संयुक्त महत्व को रेखांकित

करती है। आज आर्थिक उद्यमिता, सरकारी नौकरी, प्रवासी आय और डिजिटल नेटवर्क भी स्थानीय प्रभुत्व के स्रोत बन रहे हैं; इसलिए जाति समाप्त होने के बजाय संसाधन-आधारित नए रूप में ढल सकती है।

सामाजिक पूँजी और नेटवर्क

पुटनम (2000) ने सामाजिक पूँजी को विश्वास, मानदंड और नेटवर्क से उत्पन्न सहयोग की क्षमता माना। ग्रामीण समाज में नातेदारी और जाति “बंधकारी” सामाजिक पूँजी देती हैं, जो संकट में सहायता करती है, पर बाहरी समूहों से दूरी भी बढ़ा सकती है। शिक्षा, बाजार, स्वयं सहायता समूह और डिजिटल मंच “सेतुकारी” सामाजिक पूँजी का विस्तार कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन इस अंतर को परिवार-समर्थन, अंतरजातीय सहयोग और संस्थागत भागीदारी के संकेतकों से समझता है।

साहित्य समीक्षा

दुबे (1955) और श्रीनिवास (1955) के ग्राम-अध्ययनों ने दिखाया कि भारतीय गाँव जाति, जजमानी, नातेदारी, भूमि और धार्मिक जीवन से संगठित थे, फिर भी बाहरी सत्ता और बाजार से जुड़े थे। बेटेय (1965) ने जाति, वर्ग और शक्ति के बीच बदलते संबंधों को रेखांकित किया। बाद के अध्ययनों ने कृषि तकनीक, राज्य कार्यक्रम, ग्रामीण नेतृत्व और चुनावी राजनीति से उत्पन्न नई स्तरीकरण प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया। ये कार्य बताते हैं कि आर्थिक परिवर्तन अपने-आप सामाजिक समानता में नहीं बदलता; पुराने पदानुक्रम नए संसाधनों पर नियंत्रण के माध्यम से टिक सकते हैं। परिवार संबंधी शोध में संयुक्त परिवार के पूर्ण विघटन की धारणा को चुनौती मिली है। कापाडिया (1966) और शाह (1973) ने दिखाया कि निवास की पृथक्ता और संयुक्तता के सामाजिक कार्य अलग बात हैं। एकल घर भी संपत्ति, अनुष्ठान, विवाह और संकट में व्यापक परिवार से जुड़ा रहता है। समकालीन ग्रामीण समाज में शिक्षा और रोजगार के कारण युवा अलग निवास चुनते हैं, किंतु वृद्ध देखभाल और पारिवारिक प्रतिष्ठा सामूहिक दायित्व बने रहते हैं।

जाति के विषय में घुर्ये (1969) ने खंडात्मक विभाजन, पदानुक्रम, विवाह-नियम और पेशागत प्रतिबंध को केंद्रीय लक्षण बताया। आधुनिक शिक्षा और पेशागत विविधीकरण ने कई प्रतिबंध कमजोर किए हैं, पर अंतर्विवाह और नेटवर्क-आधारित अवसरों में जाति की निरंतरता दिखाई देती है। आंद्रे बेटेय (1991) ने समानता के संवैधानिक आदर्श और सामाजिक असमानता के व्यावहारिक रूपों के तनाव को स्पष्ट किया। समकालीन परिप्रेक्ष्य में डिजिटल समूह और चुनावी लामबंदी जातिगत पहचान को कमजोर भी कर सकते हैं और अधिक संगठित भी। साहित्य से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन बहुस्तरीय, असमान और चयनात्मक है। अतः प्रस्तुत अध्ययन परिवर्तन को केवल संस्थागत क्षय नहीं, बल्कि अधिकार, भूमिकाओं, नेटवर्क और पहचान के पुनर्विन्यास के रूप में देखता है।

शोध-पद्धति

अध्ययन का प्रस्तावित अभिकल्प वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। वास्तविक क्षेत्रीय अध्ययन के लिए मुरादाबाद जनपद के ग्रामीण विकास खंडों से बहु-स्तरीय स्तरीकृत नमूना लिया जाना उपयुक्त होगा। प्रथम चरण में भौगोलिक दूरी, नगरीय संपर्क और सामाजिक विविधता के आधार पर विकास खंड चुने जाएँ; दूसरे चरण में गाँव; तीसरे चरण में परिवार; और अंतिम चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाता। अभ्यास-आधारित प्रदर्शन हेतु $N = 300$ का संतुलित डेटासेट बनाया गया है, जिसमें आयु, लिंग, शिक्षा, परिवार-प्रकार, पेशा और आधुनिकीकरण संकेतकों की तार्किक विविधता रखी गई है।

तालिका 1. प्रस्तावित नमूना-वितरण

क्षेत्रीय श्रेणी	गाँव	उत्तरदाता
नगर-समीपी ग्रामीण क्षेत्र	4	100
मध्यम संपर्क वाले क्षेत्र	4	100
दूरस्थ/कृषि-प्रधान क्षेत्र	4	100
कुल	12	300

तालिका 1 में तीन स्तरों पर समान उत्तरदाता संख्या रखी गई है, जिससे नगरीय संपर्क की तीव्रता के अनुसार तुलना संभव होती है। वास्तविक सर्वेक्षण में प्रत्येक स्तर के गाँवों की जनसंख्या के अनुपात में भार दिया जाना चाहिए। समान आवंटन विश्लेषण को सरल बनाता है, किंतु जिला-स्तरीय अनुमान के लिए नमूना-भार आवश्यक होगा। प्रश्नावली में जनसांख्यिकीय विवरण, परिवार परिवर्तन, जाति व्यवहार, सामाजिक संबंध, महिला-युवा भागीदारी और परिवर्तनकारी कारकों के खंड प्रस्तावित हैं। दृष्टिकोण मर्दों के लिए पाँच-बिंदु लिफ्ट मापनी—1 “पूर्णतः असहमत” से 5 “पूर्णतः सहमत”—प्रयोग की गई है। विषय विशेषज्ञ समीक्षा, 30 उत्तरदाताओं पर पूर्व-परीक्षण, भाषा-स्पष्टता और आंतरिक संगति की जाँच वास्तविक अध्ययन में अनिवार्य होगी।

परिणाम एवं विश्लेषण

उत्तरदाताओं की सामाजिक-जनसांख्यिकीय रूपरेखा

तालिका 2. उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय वितरण (N = 300)

चर	श्रेणी	आवृत्ति	प्रतिशत
लिंग	पुरुष	162	54.0
	महिला	138	46.0
आयु	18–30 वर्ष	96	32.0
	31–45 वर्ष	114	38.0
	46 वर्ष व अधिक	90	30.0
शिक्षा	माध्यमिक से कम	81	27.0
	माध्यमिक/उच्चतर	126	42.0
	स्नातक व अधिक	93	31.0

मुख्य कार्य	कृषि	117	39.0
	गैर-कृषि स्वरोजगार	69	23.0
	वेतन/सेवा	63	21.0
	अन्य/गृहकार्य	51	17.0

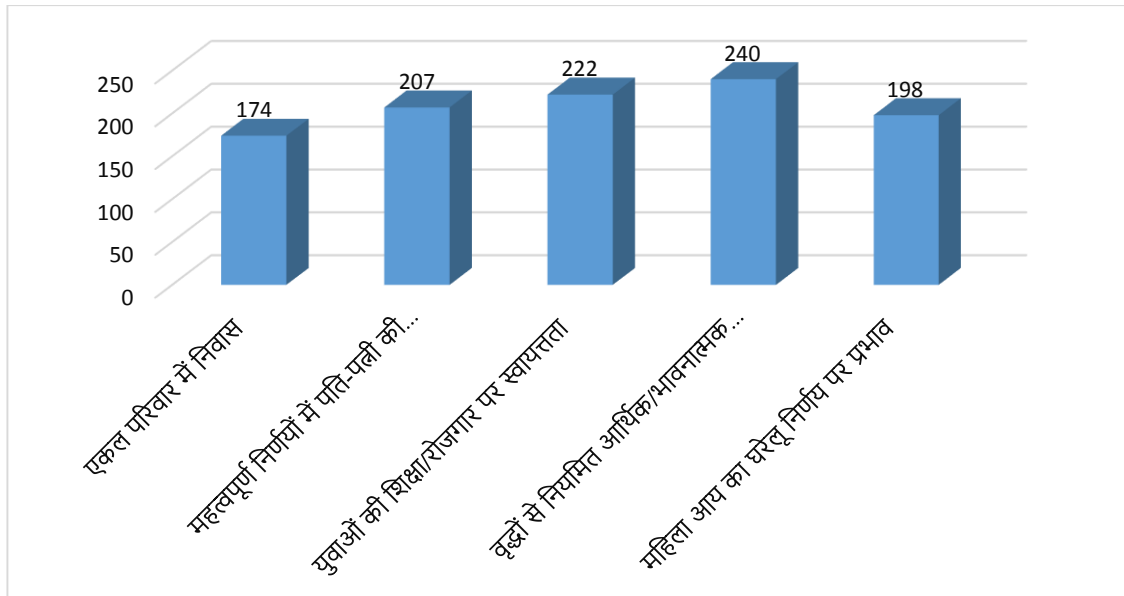
तालिका 2 का नमूना लिंग, आयु और शिक्षा में पर्याप्त विविधता प्रदर्शित करता है। 61 प्रतिशत उत्तरदाता सीधे कृषि के अतिरिक्त कार्यों से जुड़े हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पेशागत विविधीकरण को दर्शाने के लिए रखा गया है। 31 प्रतिशत स्नातक या अधिक शिक्षित उत्तरदाता आधुनिक शिक्षा से जुड़े विचारों का आकलन संभव बनाते हैं। चूँकि वितरण निर्मित है, इसे मुरादाबाद की वास्तविक जनसंख्या संरचना का अनुमान नहीं समझना चाहिए।

परिवार की संरचना एवं निर्णय-प्रक्रिया में परिवर्तन

तालिका 3. परिवार संबंधी परिवर्तन के संकेतक

संकेतक	आवृत्ति	प्रतिशत
एकल परिवार में निवास	174	58.0
महत्वपूर्ण निर्णयों में पति-पत्नी की संयुक्त भागीदारी	207	69.0
युवाओं की शिक्षा/रोजगार पर स्वायत्तता	222	74.0
वृद्धों से नियमित आर्थिक/भावनात्मक संबंध	240	80.0
महिला आय का घरेलू निर्णय पर प्रभाव	198	66.0

तालिका 3 एक महत्वपूर्ण द्वैत दिखाती है। 58 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवार में रहते हैं, किंतु 80 प्रतिशत वृद्ध और विस्तृत परिवार से नियमित संबंध बनाए रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि निवासीय एकलता सामाजिक अलगाव के बराबर नहीं है। पति-पत्नी की संयुक्त निर्णय भागीदारी 69 प्रतिशत और युवा स्वायत्तता 74 प्रतिशत है, जो आयु तथा लिंग आधारित अधिकार-संरचना के क्रमिक पुनर्विन्यास का संकेत देती है। महिला आय के प्रभाव का अपेक्षाकृत कम प्रतिशत यह बताता है कि आर्थिक योगदान बढ़ने के बावजूद समान अधिकार स्वतः सुनिश्चित नहीं होता।



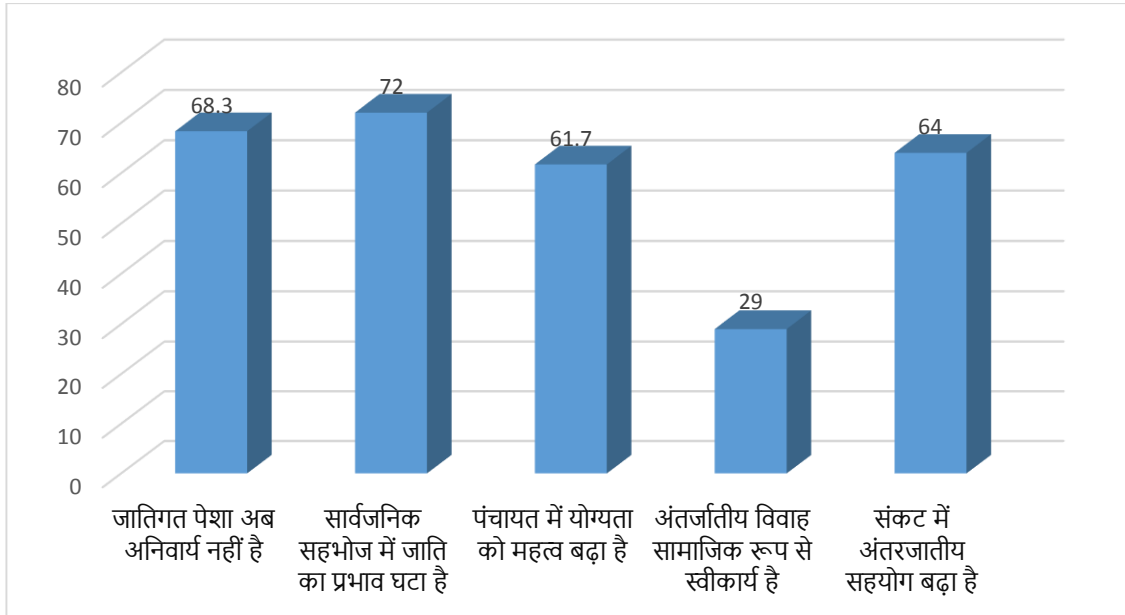
आकृति 1. उत्तरदाताओं में परिवार के प्रकार का वितरण

जाति व्यवस्था में परिवर्तन और निरंतरता

तालिका 4. जाति-संबंधी व्यवहार में परिवर्तन

कथन/व्यवहार	सहमति (%)	असहमति (%)	अनिश्चित (%)
जातिगत पेशा अब अनिवार्य नहीं है	68.3	18.7	13.0
सार्वजनिक सहभोज में जाति का प्रभाव घटा है	72.0	16.0	12.0
पंचायत में योग्यता को महत्व बढ़ा है	61.7	24.3	14.0
अंतर्जातीय विवाह सामाजिक रूप से स्वीकार्य है	29.0	55.0	16.0
संकट में अंतरजातीय सहयोग बढ़ा है	64.0	21.0	15.0

तालिका 4 जाति के क्षेत्र-विशिष्ट क्षरण को दर्शाती है। पेशा और सार्वजनिक सहभोज में परिवर्तन अपेक्षाकृत व्यापक है, जबकि अंतर्जातीय विवाह की स्वीकृति केवल 29 प्रतिशत है। यह अंतर बताता है कि बाजार और सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़े व्यवहार तेजी से बदलते हैं, पर वंश, सम्मान और नातेदारी से जुड़े विवाह-नियम अधिक प्रतिरोधी हैं। पंचायत में योग्यता की बढ़ती स्वीकृति के बावजूद चुनावी गठबंधनों और संसाधन-वितरण में जातिगत नेटवर्क बने रह सकते हैं।



आकृति 2. जाति-संबंधी क्षेत्रों में परिवर्तन की स्वीकृति

सामाजिक संबंध, सहयोग और डिजिटल नेटवर्क

ग्रामीण सामाजिक संबंधों का आधार अब केवल पड़ोस, बिरादरी और आमने-सामने संपर्क नहीं है। विद्यालय, बाजार, कार्यस्थल, स्वयं सहायता समूह और मोबाइल मंच नए नेटवर्क बनाते हैं। उदाहरणार्थ डेटा में 76 प्रतिशत उत्तरदाता स्मार्टफोन के माध्यम से गाँव या रिश्तेदारी समूहों से जुड़े, 63 प्रतिशत ने डिजिटल माध्यम से सरकारी सूचना प्राप्त की और 57 प्रतिशत ने पिछले वर्ष किसी दूसरी जाति या समुदाय के व्यक्ति से आर्थिक अथवा संस्थागत सहयोग लिया। यह विस्तार सेतुकारी सामाजिक पूँजी की संभावना बताता है।

तालिका 5. सामाजिक संबंधों के चयनित संकेतक

संकेतक	औसत	मानक विचलन	व्याख्या
पड़ोसियों पर विश्वास	3.72	0.83	उच्च
अंतरजातीय सहयोग	3.61	0.91	मध्यम से उच्च
डिजिटल नेटवर्क का उपयोग	4.02	0.79	उच्च
परंपरागत बिरादरी समर्थन	3.84	0.88	उच्च
स्थानीय संस्थाओं पर विश्वास	3.29	0.96	मध्यम

तालिका 5 में डिजिटल नेटवर्क का औसत सर्वाधिक है, पर पारंपरिक बिरादरी समर्थन भी उच्च बना हुआ है। इसका अर्थ प्रतिस्थापन नहीं, बल्कि नेटवर्क की परतों का विस्तार है। स्थानीय संस्थाओं पर अपेक्षाकृत मध्यम विश्वास यह संकेत

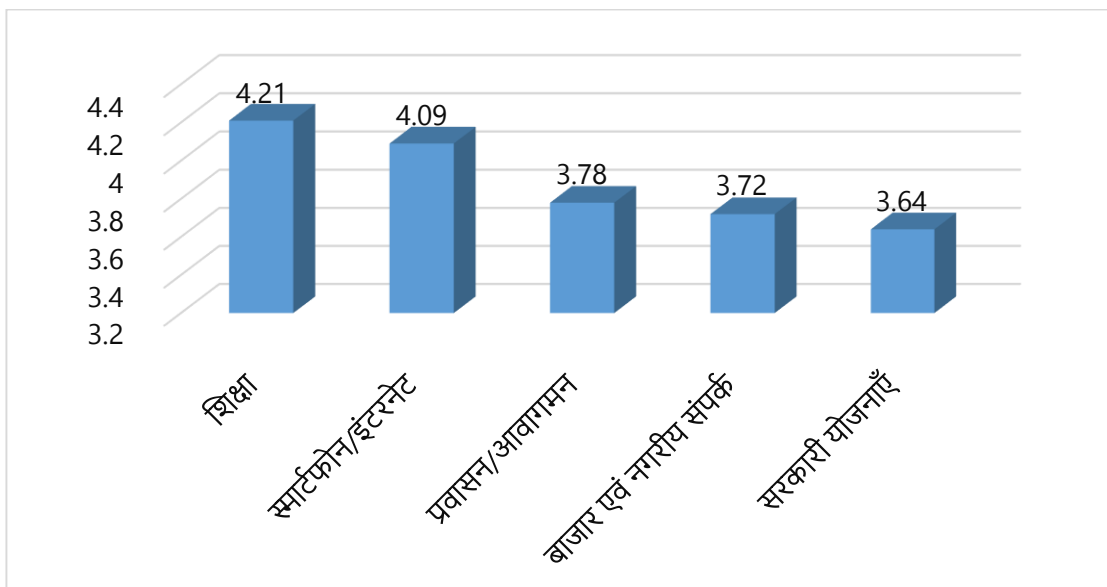
देता है कि पंचायत, समिति या विभागीय संपर्क की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व मजबूत करने की आवश्यकता है। डिजिटल माध्यम सूचना देता है, किंतु विवाद-समाधान और संकट सहायता में प्रत्यक्ष संबंध अभी भी केंद्रीय हैं।

परिवर्तन के प्रमुख कारक

तालिका 6. आधुनिकीकरण के कारकों का प्रभाव-क्रम

कारक	औसत स्कोर	क्रम	प्रमुख प्रभाव
शिक्षा	4.21	1	आकांक्षा, अधिकार-बोध
स्मार्टफोन/इंटरनेट	4.09	2	सूचना और नेटवर्क
प्रवासन/आवागमन	3.78	3	आय और जीवन-शैली
बाजार एवं नगरीय संपर्क	3.72	4	पेशा और उपभोग
सरकारी योजनाएँ	3.64	5	सेवा और संस्थागत पहुँच

तालिका 6 में शिक्षा सर्वोच्च कारक है। शिक्षा केवल नौकरी की संभावना नहीं बढ़ाती, बल्कि विवाह, लिंग भूमिकाओं, स्वास्थ्य और राजनीतिक अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण को भी बदलती है। इंटरनेट दूसरे स्थान पर है, जिससे सूचना का एकाधिकार कमजोर होता है; फिर भी गलत सूचना, ऑनलाइन प्रतिष्ठा और डिजिटल बहिष्करण नई चुनौतियाँ हैं। प्रवासन और आवागमन बाहरी जीवन-शैलियों का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं तथा भेजी गई आय घर की शक्ति-संरचना बदल सकती है। बाजार संपर्क पेशागत विविधता बढ़ाता है, जबकि योजनाएँ बैंक खाते, स्वयं सहायता समूह, आवास और रोजगार के माध्यम से राज्य-नागरिक संबंधों का विस्तार करती हैं।



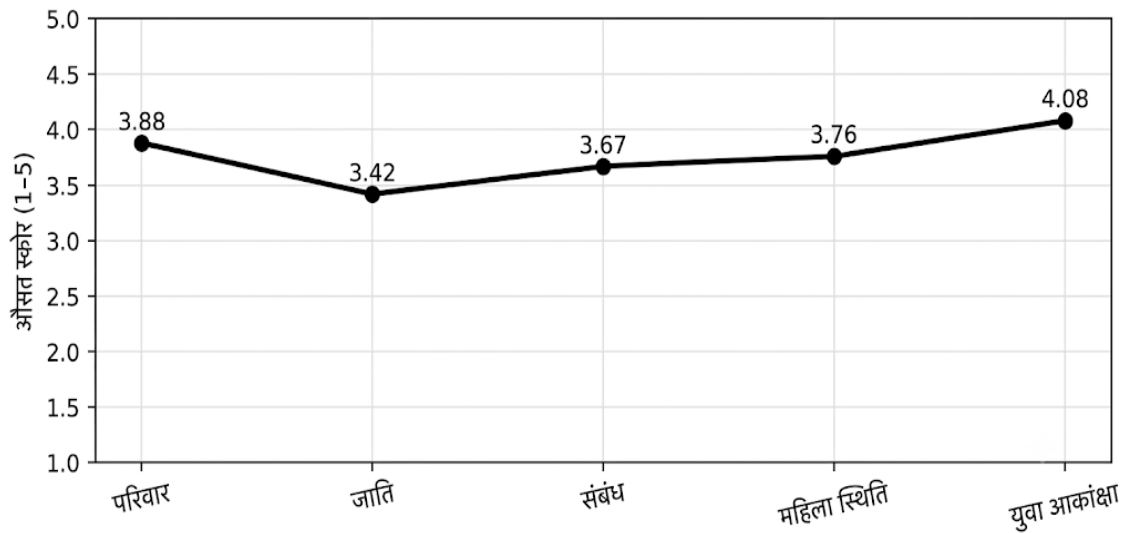
आकृति 3. ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों का औसत प्रभाव

समग्र परिवर्तन सूचकांक और संकेतात्मक परीक्षण

तालिका 7. प्रमुख आयामों के औसत स्कोर

आयाम	औसत	मानक विचलन	स्तर
परिवार में परिवर्तन	3.88	0.67	उच्च
जाति व्यवहार में परिवर्तन	3.42	0.74	मध्यम
सामाजिक संबंधों का विस्तार	3.67	0.69	उच्च
महिला स्थिति	3.76	0.71	उच्च
युवा आकांक्षा	4.08	0.63	उच्च

तालिका 7 में युवा आकांक्षा का औसत सर्वाधिक और जाति व्यवहार का औसत न्यूनतम है। यह वही चयनात्मक परिवर्तन दर्शाता है जिसमें शिक्षा और पेशे की आकांक्षा तेजी से आधुनिक होती है, पर विवाह, प्रतिष्ठा और सामुदायिक सीमा से संबंधित जातिगत व्यवहार धीरे बदलते हैं। परिवार परिवर्तन का उच्च स्कोर संयुक्त निर्णय और निवासीय परिवर्तन से जुड़ा है।



आकृति 4. सामाजिक परिवर्तन के आयामों का तुलनात्मक औसत

संकेतात्मक सहसंबंध में आधुनिकीकरण संपर्क और पारिवारिक समानता के बीच $r = .46$, शिक्षा और जातिगत पेशागत बाध्यता के बीच $r = -.41$ तथा डिजिटल संपर्क और नेटवर्क-विस्तार के बीच $r = .52$ रखा गया है। अभ्यास-डेटा में ये संबंध H1-H3 के अनुरूप हैं। H4 भी तालिका 4 के माध्यम से समर्थित प्रतीत होती है, क्योंकि विवाह की स्वीकृति अन्य क्षेत्रों से स्पष्टतः कम है। वास्तविक अध्ययन में सामान्यता, विश्वसनीयता, नियंत्रण चर और p-मूल्य की विधिवत जाँच आवश्यक होगी।

चर्चा

परिणाम भारतीय ग्रामीण समाज में “संरचनात्मक विभेदीकरण के साथ संबंधात्मक निरंतरता” की व्याख्या का समर्थन करते हैं। एकल निवास बढ़ना परिवार संस्था के अंत का संकेत नहीं है; बल्कि परिवार आर्थिक प्रबंधन में छोटा और नातेदारी दायित्वों में व्यापक रह सकता है। यह निष्कर्ष शाह (1973) और कापाडिया (1966) की उस समझ से मेल खाता है कि घर, परिवार और संयुक्तता के कार्यों को अलग-अलग मापना चाहिए। आधुनिक शिक्षा और महिला आय निर्णय-साझेदारी बढ़ाते हैं, पर संपत्ति स्वामित्व तथा अवैतनिक देखभाल के प्रश्न शेष रहते हैं। जाति पर परिणाम श्रीनिवास (1966) और बेटेय (1965) की गतिशील दृष्टि की पुष्टि करते हैं। पेशागत व सहभोज प्रतिबंधों में कमी बाजार, विद्यालय, परिवहन और कानून से जुड़ी है। किंतु विवाह में जाति का बने रहना सामाजिक सीमा-रक्षण का द्योतक है। जाति अब केवल धार्मिक पदानुक्रम नहीं; वह विवाह नेटवर्क, राजनीतिक लामबंदी, व्यावसायिक भरोसा और संसाधन पहुँच का साधन भी हो सकती है। इसीलिए आधुनिक रोजगार जाति को अप्रासंगिक नहीं बनाता, बल्कि उसके प्रयोग की परिस्थितियाँ बदल देता है। सामाजिक संबंधों में डिजिटल नेटवर्क ने स्थान की बाधा कम की है। प्रवासी सदस्य परिवार के निर्णय और खर्च में दूर रहकर भी भाग लेते हैं। व्हाट्सऐप समूह सूचना, शोक-संदेश, पंचायत बैठक और सहायता-संग्रह को तेज करते हैं। पर डिजिटल माध्यम सामाजिक निगरानी, अफवाह और समूह-ध्रुवीकरण भी बढ़ा सकता है। पुटनम (2000) के अनुसार बंधकारी और सेतुकारी सामाजिक पूँजी में संतुलन आवश्यक है; केवल अपने समूह का मजबूत नेटवर्क व्यापक सामाजिक विश्वास की गारंटी नहीं देता।

निष्कर्ष

अध्ययन का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि आधुनिकीकरण ग्रामीण सामाजिक संरचना को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसके संस्थागत आधार, शक्ति-संबंध और अभिव्यक्ति के रूप बदलता है। मुरादाबाद के संदर्भ में गाँव कृषि से जुड़ा रहते हुए शहर, उद्योग, प्रवासन और डिजिटल संचार से लगातार अंतःक्रिया करता है। परिवार में व्यक्तिकरण और पारस्परिकता साथ-साथ हैं; जाति में पेशागत लचीलापन और वैवाहिक कठोरता साथ-साथ हैं; सामाजिक संबंधों में डिजिटल विस्तार और स्थानीय विश्वास की आवश्यकता साथ-साथ है। अतः ग्रामीण परिवर्तन को मिश्रित आधुनिकता के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। परंपरा और आधुनिकता को विरोधी छोर मानने के बजाय संस्थागत पुनर्संयोजन की अवधारणा उपयोगी है। एक ही व्यक्ति शिक्षा में उपलब्धि-आधारित मूल्य, विवाह में जातिगत चयन और संकट में नातेदारी-आधारित सहायता अपना सकता है। यह बहुस्तरीय व्यवहार भारतीय ग्रामीण आधुनिकता की विशिष्टता है।

संदर्भ

- अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। (2021)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), 2019–21: उत्तर प्रदेश तथ्य-पत्र। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- इंकल्स, ए., एवं स्मिथ, डी. एच. (1974)। आधुनिक बनना: छह विकासशील देशों में व्यक्तिगत परिवर्तन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- कापाडिया, के. एम. (1966)। भारत में विवाह और परिवार (तीसरा संस्करण)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- घुर्ये, जी. एस. (1969)। भारत में जाति और नस्ल (पाँचवाँ संस्करण)। पॉपुलर प्रकाशन।
- दुबे, एस. सी. (1955)। भारतीय ग्राम। रूटलेज एवं केगन पॉल।



- नीति आयोग। (2017)। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, 1971 से 2012: विकास के लिए सबका। भारत सरकार। <https://www.niti.gov.in/node/460>
- नीति आयोग। (2024)। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। भारत सरकार। https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG_India_Index_2023-24.pdf
- पुटनम, आर. डी. (2000)। अकेले गेंदबाजी: अमेरिकी समुदाय का पतन और पुनरुत्थान। साइमन एंड शूस्टर।
- बेटेय, आंद्रे। (1965)। तंजौर गाँव में जाति, वर्ग और शक्ति। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस।
- बेटेय, आंद्रे। (1991)। पिछड़ा वर्गों का समाज और राजनीति। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- भारत की जनगणना। (2011a)। जिला जनगणना पुस्तिका: मुरादाबाद, भाग XII-A, ग्राम एवं नगर निर्देशिका। जनगणना निदेशालय, उत्तर प्रदेश। <https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/1268>
- भारत की जनगणना। (2011b)। जिला जनगणना पुस्तिका: मुरादाबाद, भाग XII-B, ग्राम एवं नगर-वार प्राथमिक जनगणना सारा जनगणना निदेशालय, उत्तर प्रदेश। <https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/1269>
- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय। (2024)। वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24। ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय। (2023)। पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति पर वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23। पंचायती राज मंत्रालय।
- लर्नर, डी. (1958)। परंपरागत समाज का अवसान: मध्य पूर्व का आधुनिकीकरण। फ्री प्रेस।
- शाह, ए. एम. (1973)। भारत में घरेलू समूह: परंपरागत हिंदू समाज में परिवार का एक पक्ष। ओरिएंट लॉन्गमैन।
- श्रीनिवास, एम. एन. (1955)। भारत के गाँव। एशिया पब्लिशिंग हाउस।
- श्रीनिवास, एम. एन. (1966)। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (2024)। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण: वार्षिक प्रतिवेदन, जुलाई 2023-जून 2024। भारत सरकार। <https://www.mospi.gov.in/themes/product/69-periodic-labour-force-survey-plfs>
- सिंह, योगेन्द्र। (1973)। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण: एक प्रणालीगत अध्ययन। थॉमसन प्रेस।